https://swadeshbhartnews

R.N.I. No. UPHIN/2021/82888

स्वदेश भारत न्यूज

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

जौनपुर से प्रकाशित

जौनपुर
मंगलवार 26 मई 2026
वर्ष : 05 – अंक : 21
पृष्ठ – 4 मूल्य – 5:00 रूपये

न्यूज कैप्सूल

सीएम विजय ने पुलिस को दिए निर्देश, अपराधियों को मिलेगी कठोरतम सजा

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पुलिस को यौन अपराधों के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की तेजी से जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कोयंबटूर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी बेरहमी से हत्या के बाद कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि जघन्य अपराधों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाए। यह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ऐसे समय में हुई है जब राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर टीवीके सरकार विपक्ष के निशाने पर है। मुख्य विपक्षी दल द्रमुक सहित विभिन्न राजनीतिक दल हत्या और यौन अपराधों की हालिया घटनाओं को लेकर सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए खुद कमान संभाली है।.

अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन आवास पर पुलिस टीम की एंट्री, अवैध निर्माण विवाद के बीच उठे सवाल

कोलकाता। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास पर पुलिस की मौजूदगी और मॉनिटर जब्त होने की खबर से हलचल मच गई है। अवैध निर्माण नोटिस और कोलकाता नगर निगम की कार्रवाई के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है, जब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित शांतिनिकेतन आवास पर सोमवार दोपहर पुलिस टीम के पहुंचने से हलचल मच गई। यह पूरा मामला उस समय और भी संवेदनशील हो गया जब कोलकाता नगर निगम द्वारा कथित अवैध निर्माण को लेकर जारी नोटिस की समय सीमा उसी दिन समाप्त हो रही थी। सूत्रों के अनुसार,कोलकाता नगर निगम ने हाल ही में अभिषेक बनर्जी की संपत्ति के कथित अवैध हिस्सों को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें जवाब देने की अंतिम तिथि सोमवार निर्धारित थी। हालांकि, रविवार को अभिषेक बनर्जी ने नगर निगम से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके बाद समय सीमा को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। सोमवार दोपहर कुछ पुलिसकर्मी, जिनमें वर्दीधारी और सादे कपड़ों में अधिकारी शामिल थे, हरीश मुखर्जी रोड स्थित शांतिनिकेतन आवास में पहुंचे। वहीं अधिकारियों ने इसे एक सामान्य और रूटीन प्रक्रिया बताया है। कुछ देर की गतिविधि के बाद अधिकारियों को एक मॉनिटर लेकर बाहर निकलते देखा गया, जिसे बाद में पुलिस वाहन में रखा गया। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने यह मॉनिटर क्यों लिया और घर के भीतर क्या जांच की गई इस पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

एनआईए ने कश्मीर में चलाया तलाशी अभियान, पूर्व जमात प्रमुख के आवास पर छापा

श्रीनगर। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार (एनआईए) ने सोमवार को जारी जांच के सिलसिले में कश्मीर के कई इलाकों में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी की कथित आतंकी गतिविधियों और राष्ट्र-विरोधी नेटवर्क के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत श्रीनगर और शोपियां जिलों के कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी में से एक कार्रवाई इमामसाहिब स्थित जामिया सिराज उल उलूम में की गई। केंद्र सरकार ने पहले इस संस्थान पर कथित आतंकी संबंधों और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने बताया कि एनआईए की एक अन्य टीम ने शोपियां जिले के मोलू चित्रगाम इलाके में पूर्व जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शहजादा औरंगजेब के आवास पर भी तलाशी ली। ये छापेमारी एनआईए, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दलों द्वारा की गई। सूत्रों ने कहा कि ये तलाशी अभियान एक जारी जांच से जुड़ा हुआ है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मामले की प्रकृति या कार्रवाई के दौरान किसी की हिरासत में लिए जाने संबंधी कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की है।

मुख्यमंत्री ने की राज्य कर विभाग की समीक्षा

बोले- राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन पर हो विशेष फोकस

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग को निर्देश दिए हैं कि कर संग्रह बढ़ाने के साथ ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान, त्वरित समाधान की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में राज्य कर विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और विभाग को राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत करना होगा।मुख्यमंत्री राज्य कर विभाग के शासन, मुख्यालय और फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाए। जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिले, अपील निस्तारण और रिफंड जैसी प्रक्रियाओं में देरी समाप्त होनी चाहिए। व्यापारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने, छोटे कारोबारियों को जागरूक करने तथा जिला एवं खंड स्तर तक करदाता सहायता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर कर चोरी रोकने के साथ वैध व्यापार को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने जीएसटी और वैट मद में कुल 1,15,977 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो पुनरीक्षित अनुमान का 98.8 प्रतिशत रहा। जीएसटी में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। बैठक में यह भी बताया गया कि जीएसटी बकाया के रूप में 2658 करोड़ रुपये जमा हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक हैं। वैट बकाया के रूप में 800 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो गत वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है। प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से 2071 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को 1,98,071 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जीएसटी का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपये तथा वैट का लक्ष्य 48,115 करोड़ रुपये है। अप्रैल में राज्य ने 10,896 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल में राज्य के अधिकांश जोनों में राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। गौतमबुद्ध नगर जोन ने 1506 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जबकि गत वर्ष इसी अवधि

के सापेक्ष इस वर्ष सहारनपुर जोन में 35.1 प्रतिशत और वाराणसी प्रथम जोन में 33.2 प्रतिशत वृद्धि रही। मुरादाबाद जोन ने अप्रैल 2025 के सापेक्ष अप्रैल में बढ़ोतरी दर्ज की। फर्जी फर्मों और कर चोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। बोगस फर्मों के खिलाफ 477 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई तथा 168 गिरफ्तारियां की गईं। 7 नवंबर 2025 को एसआईटी का गठन किया गया। 180 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की गई तथा न्यायनिर्णयन कार्रवाई से 2250 करोड़ रुपये की मांग सृजित हुई। अपील निस्तारण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2025-26 में जीएसटी की 52,432 और वैट की 11,365, कुल 63,797 अपीलों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में जीएसटी की 18,504 तथा वैट की 2,193, कुल 20,697 अपीलें विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ देश में सबसे अधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बन गया है। जीएसटी पंजीयन आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि प्रदेश में 8 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14 दिन है। प्रदेश में 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था लागू है। रिटर्न दाखिले की स्थिति में भी प्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे है। देय तिथि तक 90 प्रतिशत से अधिक करदाता रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जबकि औसत मासिक रिटर्न दाखिला प्रतिशत प्रदेश में 93 प्रतिशत और केंद्र स्तर पर 91 प्रतिशत है। बीते महीनों के 99 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दाखिल कराए जा चुके हैं। जीएसटी रिफंड मामलों के निस्तारण की औसत अवधि उत्तर प्रदेश में 27 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 48 दिन है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रिफंड व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए ताकि व्यापारियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित न हो। तकनीक आधारित कर प्रशासन के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि 16 पैरामीटर निर्धारित कर 1.59 लाख वार्षिक रिटर्नों में मिसमैच डेटा पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

नड्डा ने देश में तैयारियों का जायजा लिया, लोगों को इबोल से सतर्क रहने की सलाह

नई दिल्ली।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इबोला वायरस रोग (ईवीडी) की तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों की समीक्षा की। यह समीक्षा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हाल ही में सामने आए प्रकोपों के मद्देनजर की गई है। भारत में इबोला का कोई भी मामला अब तक दर्ज नहीं किया गया है।

संभावित खतरे से निपटने के लिए कैसी हैं तैयारियां?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किया है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (अफ्रीका सीडीसी) ने भी इसे महाद्वीपीय सुरक्षा का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईसीएस) बताया है। नड्डा ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान देश में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी की तैयारी

केंद्र सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक प्रतिक्रिया उपायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता बढ़ाने और निगरानी को तेज करने के लिए भी चर्चा हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। यह

सुनिश्चित किया जाएगा कि देश इबोला के लिए पूरी तरह तैयार रहे।

बैठक में कौन अधिकारी शामिल हुए?

समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव उपस्थित थे। आईसीएमआर के महानिदेशक और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) भी मौजूद रहे। अतिरिक्त सचिव (जन स्वास्थ्य) और एनसीडीसी के निदेशक ने भी इसमें भाग लिया। मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए।

एक्शन मोड में बंगाल सीएमः 2021 चुनाव में हुई हिंसा का भी हिसाब लेंगे शुभेंदु, कहा- हर घटना की कराएंगे जांच

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को नंदीग्राम में आयोजित धन्यवाद सभा के दौरान बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों का पूरा हिसाब लिया जाएगा और सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी कि वे कानून अपने हाथ में न लें।

सीएम शुभेंदु ने क्या चेतावनी दी?

अपने गढ़ नंदीग्राम में समर्थकों को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 2021 चुनाव के बाद राज्य के कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और कई समर्थकों की हत्या तक कर दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हर घटना का रिकॉर्ड रखा है और अब सभी मामलों में

न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि अगर आप चाहें तो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों की ईंट तक निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करना। भाजपा इस तरह की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती। मुझे सब याद है और किसी भी घटना को अनदेखा नहीं किया जाएगा। शुभेंदु के इस बयान को बंगाल की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। 2021 चुनाव के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर बड़े पैमाने पर हिंसा कराने का आरोप लगाया था। उस समय कई मामलों को लेकर अदालतों तक में सुनवाई हुई थी और यह मुद्दा भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया था। सभा के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत के बावजूद पिछली सरकार ने पीड़ित परिवारों की कोई मदद नहीं की। ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने उन्हें दो बार चुनाव हारने वाली मुख्यमंत्री बताया।

'Gen-Z तोड़ेंगे पीएम मोदी का अहंकार': राहुल गांधी

नई दिल्ली। सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी-प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्थान को गड़बड़ी का प्रतीक बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि आज की युवा पीढ़ी यानी जेन जी प्रधानमंत्री के अहंकार को चकनाचूर कर देगी।

क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर हिंदी में एक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इतने गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस साल 18.5 लाख छात्र परीक्षाओं में शामिल हुए थे। पिछले एक हफ्ते से छात्र ऑन-स्क्रीन मार्किंग

में गलतियों और मूल्यांकन में गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि इन शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं।कांग्रेस नेता ने एक 17 साल के छात्र का जिक्र किया जिसकी उत्तर पुस्तिका का गलत मूल्यांकन हुआ था। राहुल ने कहा कि जब उस छात्र ने न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया का सहारा लिया, तो उसे मदद मिलने के बजाय गालियां दी गईं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के आईटी सेल ने उस छात्र को देशद्रोही, 'सोरोस एजेंट' और 'डीप स्टेट' का हिस्सा बता दिया। राहुल ने कहा कि जब एक बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है, तो भाजपा उसे गद्दार कहती है।राहुल गांधी ने आगे कहा कि सच तो यह है कि मोदी सरकार युवाओं और जेन जी से डरती है क्योंकि वे अब सवाल पूछने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी सवाल पूछने की हिम्मत करता है, यह सरकार उसे बदनाम करती है और डराकर कुचल देती है। राहुल ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि यही युवा आपका अहंकार तोड़ेंगे।इस विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को बड़ा कदम उठाया। मंत्रालय ने कहा कि सीबीएसई अपने पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को ठीक करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की मदद लेगा।

असम में पेश हो गया यूसीसी विधेयक, हिमंत सरमा सरकार का बड़ा कदमय आदिवासियों को राहत

गुवाहाटी। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर दिया गया है। विपक्षी दलों के विधायकों ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। विपक्ष ने विधेयक पेश किए जाने से पहले सभी पक्षकारों के साथ व्यापक चर्चा की मांग की है। बता दें कि कैबिनेट ने इस विधेयक को पहले ही हरी झंडी दे दी थी। इसके साथ ही इस विधेयक को सदन के पटल पर रख दिया गया। उत्तराखंड, गुजरात के बाद असम तीसरा राज्य है जिसने यूसीसी बिल पेश किया है। इस विधेयक में आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मसौदा विशिष्ट जनसांख्यिकीय विविधता को ध्यान में रखकरतैयार किया गया है। इसके चार प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है राज्य में बहुविवाह की प्रथा पर पुरी तरह से रोक लगाना। दूसरा है विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र की सीमा को लागू करना। तीसरा है सभी शादियों और तलाक का सरकारी रिकॉर्ड में द्रज किया जाना। चौथा उद्देश्य बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक दिलवाना और पांचवां लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए कड़े नियम बनाना और पंजीकरण अनिवार्य करना है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह कानून धार्मिक परंपराओं और पूजा पद्धतियों में कोई दखल नहीं देना वाला है। इसके जरिए किसी भी धार्मिक रीति-रिवाज को नियंत्रित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में सवाल हैं कि क्या पूजा-पाठ और रीति रिवाज भी यूसीसी के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा, धार्मिक परंपराओं को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी और मैदानी इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय को भी यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

मुनंबम वक्फ भूमि विवादः 'नहीं होगी बेदखली, लोगों को उनकी जमीन मिलेगी' : सीएम सतीशन

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने सोमवार को आश्वासन दिया है कि मुनंबम भूमि विवाद से प्रभावित निवासियों को उनकी जगहों से बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भूमि पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा, 'हमने यह फैसला लिया है कि इन पीड़ितों को उनकी जगहों से बेदखल नहीं किया जाएगा। उनकी रक्षा की जाएगी। उन्हें उनकी भूमि मिलेगी। हम अंत तक इसके लिए लड़ेंगे।' उन्होंने कहा कि यह रुख नया नहीं है और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने विपक्ष में रहते हुए भी लगातार इसी रुख को बनाए रखा था। सतीशन ने वक्फ बोर्ड के विवादित भूमि को उम्मीद (ऊईउ) पोर्टल पर पंजीकृत करने के

फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने दावा किया कि बोर्ड की नियुक्तियां पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के कार्यकाल में की गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य वर्तमान यूडीएफ सरकार को इस मुद्दे को 10 मिनट के भीतर हल करने से रोकना था, जैसा कि उन्होंने पहले वादा किया था। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी केरल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के. एस. हमजा द्वारा यह दोहराने के एक दिन बाद आई है कि मुनंबम की विवादित भूमि वक्फ संपत्ति है और इसे राज्य की अन्य वक्फ संपत्तियों के साथ उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। मुनंबम भूमि विवाद केरल में एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बनकर उभरा है, जिसमें कई निवासी अपनी भूमि की स्वामित्व स्थिति को लेकर चिंता जता रहे हैं। भाजपा ने विरोध कर रहे निवासियों को समर्थन दिया है और दावा किया है कि संशोधित वक्फ अधिनियम उनकी चिंताओं को दूर करने में मदद करेगा।

क्वॉड से पहले विश्वास बहाली में जुटे दिखे रूबियो, अमेरिका फर्स्ट के जवाब में जयशंकर बोले इंडिया फर्स्ट

नई दिल्ली। क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले मार्को रूबियो पिछले दो दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके भारत-अमेरिका संबंधों को संभालने की गंभीर कोशिश करते दिखाई दिए। ट्रंप प्रशासन की शुल्क नीतियों, पाकिस्तान से जुड़े घटनाक्रमों और ईरान युद्ध के बाद उपजे संकट ने दोनों देशों के बीच भरोसे की जिस कमी को जन्म दिया था, रूबियो दिन भर अपने बयानों से उसे पाटने का प्रयास करते दिखे। बयानों को बारीकी से देखें, तो साफ होता है कि रिश्ते जितने रणनीतिक हैं, उतने ही जटिल भी हो चुके हैं। ट्रंप की अनिश्चित कूटनीति ने सवाल पैदा किया है कि क्या वॉशिंगटन एक भरोसेमंद दीर्घकालिक साझेदार है। मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के व्यापारिक फैसले किसी देश विशेष को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि

अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए लिए गए थे। यह बयान इसलिए दिया गया क्योंकि भारत में यह धारणा बन रही थी कि ट्रंप प्रशासन चीन के साथ समीकरण सुधारने और पाकिस्तान के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाने के बीच भारत को उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहा।

अमित शाह का सीमावर्ती राज्यों का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा, जवानों से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार रात से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के एक बड़े दौरे पर निकल रहे हैं। इस दौरे का मकसद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाना है। केंद्र सरकार बदलते सुरक्षा खतरों को देखते हुए सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर लगातार ध्यान दे रही है। यह दौरा उसी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है।

राजस्थान से होगी दौरे की शुरुआत

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्यों का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में शाह 25 मई सोमवार की रात को राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे। यहां से उनके विस्तृत दौरे की शुरुआत होगी।

जवानों से करेंगे मुलाकात

26 मई को गृह मंत्री भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे। यहां वह सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान वह कठिन परिस्थितियों में तैनात

जवानों की समस्याओं और जमीनी हकीकत को समझेंगे। शाह जवानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इन योजनाओं का मकसद कठिन इलाकों में सेवा दे रहे जवानों का मनोबल बढ़ाना और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करना है।

बीकानेर में होगी उच्च स्तरीय बैठक

दौरे के दौरान अमित शाह बीकानेर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, बीएसएफ के बड़े अफसर और पांच सीमावर्ती जिलों के पुलिस प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पार से होने वाले खतरों से निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान के बाद अमित शाह 29 मई को गुजरात के भुज जाएंगे। वहां वह एक अन्य सीमा चौकी का निरीक्षण करेंगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र का दौरा करेंगे। कच्छ के रण में स्थित यह इलाका घुसपैठ के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। इसके बाद 5 जून को वह त्रिपुरा जाएंगे। वहां वह भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसी चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। जून के मध्य में गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद यह उनका पहला महत्वपूर्ण दौरा होगा। यहां वह सीमा पर निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए किए जा रहे कामों का मूल्यांकन करेंगे। इस पूरे दौरे का उद्देश्य आधुनिक तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाना है।

धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, कला, खेल और चिकित्सा जगत की 66 हस्तियों को मिले पद्म सम्मान

नई दिल्ली। इस साल जनवरी में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, इनमें से 66 हस्तियों को आज सम्मानित किया जा रहा है। इस साल की सूची के मुताबिक कुल पांच लोगों को पद्म विभूषण, 13 विभूतियों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री से नवाजा जाएगा।पद्म विभूषण सम्मान 2026 में सबसे पहले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) को प्रदान किया गया। यह सम्मान उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने ग्रहण किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी नेतृत्व क्षमता में भारतीय टीम ने इस वर्ष वनडे वर्ल्ड कप जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। सोलर ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी क्रम में पुदुचेरी के सिलंबम खिलाड़ी के. पजनीवेल को पारंपरिक मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा,

यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममिडाला जगदीश कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान किया गया।

पद्म सम्मान हर साल क्यों दिए जाते हैं?

कला, समाज सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान सहित कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाली हस्तियों को हर वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण सेवा, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए है। पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर होती है।

सम्पादकीय

टीएमसी की उम्मीद गलत साबित हुई

टीएमसी की ये उम्मीद गलत साबित हुई कि बांग्ला अस्मिता की प्रतिनिधि के रूप में खुद पेश कर वह 'हिंदुत्व- हिंदीऽ पहचान वाली भाजपा को जीतने से रोक देगी। असम में ऐसी सोच पहले ही गलत साबित हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का सियासी किला फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2026 का विधानसभा चुनाव युद्ध के अंदाज में लड़ा। अपने पास मौजूद तमाम गोले तो उसने वहां दागे ही, केंद्र में सत्ताधारी होने के नाते शासन तंत्र से हासिल होने वाली ताकत एवं प्रभाव का भी बेहिचक उपयोग किया। अपनी खास जूझारू भावना के लिए चर्चित ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेर लेने की ये रणनीति कामयाब रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की विवादास्पद प्रक्रिया से तृणमूल कांग्रेस के लिए मुकाबले का धरातल असमान हो जाने के संकेत लगातार मिल रहे थे। निर्वाचन आयोग के अन्य कदमों ने टीएमसी की राह को और भी कठिन बनाया। अन्य संवैधानिक संस्थाओं ने भी चुनाव प्रक्रिया पर उठे प्रश्नों की फिक्र नहीं की। 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद किसी नेता या पार्टी के लिए चुनावी मुकाबला वैसे भी आसान नहीं रह जाता। एंटी-इन्कबेंसी से उत्पन्न चुनौतियां उसके सामने खड़ी होती हैं। ये सारे पहलू मिलकर इस बार ममता बनर्जी पर भारी पड़े। टीएमसी की ये उम्मीद कमजोर जमीन पर खड़ी नजर आई कि बांग्ला अस्मिता की प्रतिनिधि के रूप में खुद पेश कर वह 'हिंदुत्व- हिंदीऽ पहचान वाली भाजपा को जीतने से रोक देगी। असम में ऐसी सोच एक दशक पहले ही गलत साबित हो चुकी थी। अब वहां भाजपा ने जीत की हैट-ट्रिक बनाई है। इस बार वह और बड़े बहुमत से सत्ता में लौट रही है। यह इस समझ की पुष्टि है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में उग्र हिंदुत्व और कैश ट्रांसफर के जरिए मतदाताओं को लुभाने की रणनीति वहां कामयाब बनी हुई है। इसके अलावा संभव है राज्य में हुए विवादास्पद परिसीमन का लाभ भी भाजपा को मिला हो। वैसे, इन बातों की आड़ लेकर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को जनता से दूर रहते हुए सियासत करने (टीएमसी अभी तक इसका अपवाद है) की अपनी कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें देर-सबेर यह समझना होगा कि उनका मुकाबला बुल्डोजर जैसी एक चुनाव मशीनरी से है, जो जीत की राह में किसी नैतिक बाधा से बंधी हुई नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर संजीवनी बना डायल 1033

कल्पना कीजिए, आप एक खूबसूरत सफर पर हैं। चारों तरफ फैली खुली शानदार सड़क, रफ्तार पकड़ती गाड़ी और गुनगुनाता सुहाना मौसम। सब कुछ एकदम मुकम्मल लगता है। लेकिन अचानक, अगले ही मोड़ पर कोई अनहोनी हो जाए...। कई बार हाइवे पर हुआ एक अनचाहा हादसा पल भर में जिंदगी की खुशियों को मातम में बदल देता है। ऐसे किसी अनजान और सुनसान सफर पर, जहां दूर-दूर तक कोई अस्पताल या मदद नजर नहीं आती, वहां मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता एक नंबर उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरता है- 1033। आज देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह चार अंकों का नंबर महज एक हेल्पलाइन नहीं, बल्कि हजारों-लाखों मुसाफिरों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है।

संकट के समय फरिश्ता बनती है एक कॉल

हाइवे पर दुर्घटना होने के बाद जो सबसे पहला घंटा होता है, उसे चिकित्सा विज्ञान में गोल्डन ऑवर कहा जाता है। इस एक घंटे के भीतर अगर घायल को सही इलाज मिल जाए, तो उसकी जान बचने की संभावना 80 फीसदी तक बढ़ जाती है। 1033 इसी गोल्डन ऑवर का रक्षक है।

जैसे ही कोई इस नंबर पर डायल करता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का कॉल सेंटर तुरंत हरकत में आ जाता है। जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए हादसे की सटीक लोकेशन ट्रेस की जाती है और चंद मिनटों के भीतर एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है। घायलों को नजदीकी ट्रॉमा सेंटर या अस्पताल पहुंचाया जाता है। साथ ही रास्ता साफ करने के लिए क्रेन और पेट्रोलिंग गाड़ियां तैनात हो जाती हैं।

महज 7 से 10 मिनट में आ गई एम्बुलेंस

एनएचएआई के 1033 सेवा का लाभ लेने वाले श्री नितिन वर्मा बताते हैं, मैं रायपुर से बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में सफ़र कर रहा था। दोपहर 2 बजे के करीब हाइवे पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मोबाइल में नेटवर्क भी कम था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां हूं? मैंने 1033 लगाया, और महज 7 से 10 मिनट में एम्बुलेंस मेरे सामने थी। वो नंबर नहीं, मेरे लिए संजीवनी से कम नहीं था।

सिर्फ हादसा नहीं, हर मुश्किल का हल है 1033

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि यह नंबर सिर्फ एक्सीडेंट के समय काम आता है, लेकिन असल में यह हाइवे पर आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। आप कई विपरीत स्थितियों में भी इसकी मदद ले सकते हैं। रात के सन्नाटे में अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या इंजन फेल हो जाए, हाइवे पर कोई पेड़ गिर गया हो, मवेशी आ गए हों या कोई भारी मलबा पड़ा हो, यात्रा के दौरान अगर अचानक किसी सहयात्री की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ जाए, टोल प्लाजा या फास्टैग संबंधी कोई समस्या हो या हाइवे पर असुरक्षा महसूस हो रही हो... तो भी 1033 सेवा का लाभ लिया जा सकता है।

अनुभवों की जुबानी, संजीवनी की कहानी

रात के सन्नाटे में भारी ट्रक का टायर फटा, 1033 ने दी राहत

ट्रक ड्राइवर श्री गुरदीप सिंह अपने अनुभव साझा करते हैं, बात रात के करीब 09:45 बजे की है। मैं अपना भारी-भरकम ट्रक लेकर रायपुर से बिलासपुर की ओर बढ़ रहे था। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ ट्रक का टायर फट गया। भारी वाहन और ऊपर से रात का सन्नाटा... ऐसी स्थिति में हाइवे के किनारे ट्रक खड़ा करना और मदद ढूंढना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। मैंने बिना वक्त गंवाए 1033 पर कॉल किया। एनएचएआई की टीम ने तुरंत मेरी लोकेशन ट्रेस की और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने न सिर्फ क्रेन और तकनीकी मदद का इंतजाम किया, बल्कि जब तक काम पूरा नहीं हुआ, वहां सुरक्षा सुनिश्चित की, ताकि कोई और बड़ा हादसा न हो।

जब जाम हो गया चक्का तो पेट्रोलिंग टीम ने बढ़ाया मदद का हाथ

बिलासपुर-नागपुर रूट के मुसाफिर श्री एस.पी. चौबे ने बताया, हम अपनी कार से सफर कर रहे थे कि अचानक गाड़ी पंचर हो गई। जब स्टेपनी बदलने की बारी आई, तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। बहुत दिनों से पहिया खुला नहीं था, इसलिए वह बुरी तरह जाम हो चुका था। मेरा ड्राइवर पसीने से तर-बतर होकर उसे खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। हाइवे के किनारे खड़ी

हमारी गाड़ी और ड्राइवर की जद्दोजहद को वहां से गुजर रही 1033 की रूट पेट्रोलिंग व्हीकल टीम ने खुद देख लिया।

टीम के जवान तुरंत हमारे पास रुके। उन्होंने न सिर्फ अपनी गाड़ी से जरूरी हैवी टूल्स (औजार) निकाले, बल्कि खुद आगे बढ़कर जाम हो चुके चक्के को खोला, टायर बदला और हमारी गाड़ी को रवाना किया। उनके इस अपनेपन और मुस्तैदी ने हमारा दिल जीत लिया।

भारी ट्रेलर का ब्रेक हुआ जाम, मुस्तैदी से टला बड़ा खतरा

हाइवे पर सुरक्षा सिर्फ छोटे वाहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारी-भरकम कमर्शियल वाहनों के लिए भी 1033 एक सुरक्षा कवच है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर से महासमुंद की ओर जा रहे विशाल ट्रेलर के ड्राइवर श्री शिवम यादव के साथ हुआ। उनके ट्रेलर का ब्रेक अचानक जाम हो गया और गाड़ी में जरूरी एयर प्रेशर नहीं बन पा रहा था। बीच हाइवे पर इतने बड़े वाहन का इस तरह रुकना बेहद खतरनाक था।

सूचना मिलते ही 1033 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। भारी ट्रेलर के पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ियों को सचेत करने के लिए टीम ने सेफ्टी कोन और चेवरॉन साइन बोर्ड लगाए, ताकि एक सुरक्षित बफर जोन बन सके। इस हाई-प्रोफेशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से न तो हाइवे पर जाम लगा और न ही कोई दुर्घटना हुई। ट्रेलर को सुरक्षित तरीके से सुधरवाने की व्यवस्था की गई।

सरल, आसान और सुविधाजनक

1033 की सबसे खास बात इसकी सरलता और गति है। यह सेवा 24 घंटे, सातों दिन काम करती है। इसमें भाषा की कोई दीवार नहीं है। स्थानीय भाषाओं से लेकर हिंदी और अंग्रेजी, हर भाषा में यहां मदद मिलती है। टोल-फ्री होने के कारण मोबाइल में बैलेंस न होने पर भी इस पर कॉल की जा सकती है।

बदलते भारत के साथ हमारे हाइवे आधुनिक और हाई-स्पीड हो रहे हैं, लेकिन रफ्तार के इस दौर में सुरक्षा सबसे अहम है। अगली बार जब आप किसी लंबे सफर पर निकलें, तो अपनी गाड़ी की डिक्की चेक करने के साथ-साथ अपने दिमाग और मोबाइल की स्पीड डायल लिस्ट में 1033 को जरूर सेव कर लें। क्योंकि जब हाइवे पर मुश्किलें रास्ता रोकती हैं, तो यही चार अंक संजीवनी बनकर जिंदगी की रफ्तार को थमने नहीं देते।

कठिनाइयां ही हमें असाधारण बनाती हैं

जब खेल आसान हो, तब मैदान में उतरना बड़ी बात नहीं। असली पहचान तब होती है, जब आसमान धुंधला हो, शरीर थक चुका हो, भीड़ की आवाज धीमी पड़ जाए और स्कोरबोर्ड तुम्हारे खिलाफ खड़ा दिखाई दे। वही क्षण आदमी को बताता है कि वह वास्तव में कौन है। मैंने अपने खिलाड़ियों से हमेशा कहा है कि तुम्हारी ताकत इस बात से नहीं देखी जाएगी कि तुमने कितनी बार जीत हासिल की, बल्कि इस बात से देखी जाएगी कि हार सामने खड़ी होने पर भी तुमने अपने कदम कितनी मजबूती से रखे। सामान्य दिनों में तो हर कोई आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है, लेकिन मुश्किल दिन ही आदमी के भीतर छिपी ताकत और साहस को बाहर निकालते हैं। तुम मैदान में उतरते हो, तो केवल गेंद लेकर नहीं उतरते। तुम अपने परिवार की उम्मीदें और इससे भी ज्यादा अपने भीतर उस छोटे-से विश्वास को लेकर उतरते हो, जो यह कहता है कि-'मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं।' मैंने ऐसे खिलाड़ियों को देखा है, जो शरीर से तो लंबे-चौड़े-बलिष्ठ थे, पर संकट आते ही उनका साहस डगमगाने लग जाता था। जीत केवल ताकत से नहीं मिलती, जीत तो उस आदमी के हिस्से आती है, जो कठिनाई को देख कर पीछे नहीं हटता।जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, तब दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक वे लोग जो बहाने खोजते हैं, जैसे- मौसम खराब था, किस्मत साथ नहीं थी। और दूसरे वे लोग, जो अपने जूतों के फीते कसते हैं और कहते हैं 'अब मेरी बारी है यह दिखाने की कि मैं किस मिट्टी का बना हूं।' एक समय के बाद मन हार मानने के लिए बहाने देने लगता है। तभी चरित्र खेल में उतरता है। चरित्र वह शक्ति है, जो कहती है 'एक कदम और।' और वही अतिरिक्त कदम इतिहास बनाता है। जीवन कठोर है। कभी पूरी तैयारी के बाद भी हार जाओगे। कभी तुम्हारे अपने साथी तुम्हें कमजोर कहेंगे। लेकिन यह तो तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी आत्मा का कप्तान कौन है- हालात या तुम स्वयं। तूफान जब आता है, तब कमजोर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ और गहरे धंस जाते हैं। आदमी भी ऐसा ही है। संकट उसे तोड़ता नहीं, संकट उसके भीतर की असली ताकत को बाहर लाता है। मैंने अपने खिलाड़ियों से हमेशा यही कहा- भीड़ की आवाज को मत सुनो। केवल अपने भीतर की आवाज सुनो। अगर तुम्हारा मन अभी भी लड़ने को तैयार है, तो खेल समाप्त नहीं हुआ। अगर रास्ता कठिन न हो, तो मंजिल की कीमत भी कम हो जाती है। इसलिए कठिनाई से घबराओ मत। उसका स्वागत करो, क्योंकि वही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। लोग तुम्हें तुम्हारी आसान जीतों से कुछ समय के लिए याद रखेंगे, लेकिन वे तुम्हें हमेशा उस साहस के लिए याद रखेंगे, जो तुमने सबसे कठिन क्षणों में दिखाया था। इसलिए जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तब सिर झुका कर मत बैठो। दुनिया को बता दो कि मजबूत लोग कठिनाइयों से भागते नहीं, वे कठिनाइयों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वही क्षण उन्हें महान बनाते हैं।

सूत्र- बहाने छोड़ आगे बढ़ें

जब आसमान धुंधला लगे, तब याद रखना कि असली पहचान जीत में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में है, जिससे तुम हार के सामने खड़े रहते और भीतर की आवाज सुनकर एक कदम और बढ़ाते हो, क्योंकि कदम तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। इसलिए बहाने छोड़ आगे बढ़ें, क्योंकि संकट तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आता है। आप अपने जीवन के कप्तान खुद बनें।

जैव विविधता, जल संरक्षण और जनभागीदारी का अनूठा संगम

धनंजय राठौर, अशोक कुमार चंद्रवंशी

छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय आज पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और सामुदायिक सहभागिता का प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभर रहा है। जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2026 की थीम स्थानीय स्तर पर कार्य, वैश्विक प्रभाव को यह जलाशय वास्तविक रूप में साकार कर रहा है। सुबह के शांत वातावरण में प्रवासी पक्षियों की मधुर आवाजें और जलाशय के आसपास आजीविका से जुड़े ग्रामीणों की गतिविधियां प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाती हैं। कोपरा जलाशय वर्षों से क्षेत्र के लोगों के लिए जल, मत्स्य पालन, कृषि और पर्यावरणीय संतुलन का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संरक्षण कार्यों को मिली नई गति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता संरक्षण, आर्द्रभूमि विकास और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल स्रोतों के संरक्षण, वृक्षारोपण, वन्यजीव सुरक्षा और सामुदायिक भागीदारी से जुड़े कई अभियान प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव कोपरा जलाशय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है।

स्थानीय समुदाय निभा रहे अहम भूमिका

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता राज्य की अमूल्य धरोहर है और इसके संरक्षण

में स्थानीय समुदायों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोपरा जलाशय यह संदेश देता है कि जब शासन और समाज मिलकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेते हैं, तब पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होता है।

प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित आश्रय

कोपरा जलाशय हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। हर वर्ष विभिन्न देशों और राज्यों से आने वाले पक्षी यहां भोजन और विश्राम प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही यह जलाशय जलीय जीवों, मछलियों, वनस्पतियों और अनेक सूक्ष्म जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है। इसी विशेषता के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता मिली है।

स्वच्छता, वृक्षारोपण और बायो-फेंसिंग पर विशेष जोर

स्थानीय ग्रामीणों, महिला स्व-सहायता समूहों, युवाओं और विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी से यहां स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, पक्षी संरक्षण और बायो-फेंसिंग जैसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलने के साथ लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हो रही है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी महत्वपूर्ण

विशेषज्ञों के अनुसार आर्द्रभूमियां प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती हैं। वे बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, जल शुद्धिकरण और कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में कोपरा जलाशय का संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी बेहद उपयोगी साबित हो रहा है।

सतत विकास का बन रहा राष्ट्रीय मॉडल

कोपरा जलाशय आज यह संदेश दे रहा है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की साझा जिम्मेदारी है। स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे-छोटे प्रयास ही वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव की नींव बनते हैं। छत्तीसगढ़ का यह पहला रामसर स्थल आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और सामुदायिक सहभागिता का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी है। इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और इसके वैश्विक महत्व पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के नागरिकों और संरक्षण टीम की सराहना करते हुए अपना संदेश दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि कोपरा जलाशय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रामसर स्थल की मान्यता मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। हमारी सरकार जैव विविधता संरक्षण, आर्द्रभूमि के विकास और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कोपरा जलाशय इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब शासन की नीतियां और समाज का संकल्प एक साथ मिलते हैं, तो स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे प्रयास भी वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमारी समृद्ध प्रकृति ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य है।

(लेखक संयुक्त संचालक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं)

बालेंद्र शाह का नया प्रोटोकॉलः नेपाल की विदेश नीति में बड़े बदलाव और कूटनीतिक चुनौतियां

डॉ. ऋषि गुप्ता

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह किसी न किसी मामले के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नेपाल में जेन-जी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बनने से लेकर चुनावों में शानदार प्रदर्शन तक उनका नाम छाया रहा। युवाओं ने उन पर भारी भरोसा जताया और उनकी विजय से ऐसा माना गया कि वे नेपाली राजनीति के पुराने एवं कमजोर किले को तोड़कर एक नवयुगीन भव्य इमारत का निर्माण करेंगे, जिसके स्तंभ भ्रष्टाचार और विदेशी प्रभाव से अलग पारदर्शिता और संप्रभुता से ओतप्रोत होंगे। पिछले दो महीनों में इस दिशा में उन्होंने कुछ बड़े नीतिगत बदलाव भी किए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन प्रोटोकाल और सामान्य शिष्टाचार की व्यवस्था से जुड़ा है। प्रोटोकाल में उनका आग्रह है कि वे अपने समकक्ष विदेशी पदधारकों से ही मुलाकात करेंगे। ज्ञात हो कि पिछली सरकारों में प्रधानमंत्री प्रोटोकाल की इस परंपरा के पालन में विफल रहे, जिसके चलते उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। बालेंद्र शाह इस परिपाटी को बदलना चाहते हैं। परिवर्तन के इसी क्रम में बीते दिनों उन्होंने नेपाल आए कुछ विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और विशेष दूतों से भी मिलने से इसलिए इन्कार कर दिया, क्योंकि वे उनके पद और प्रोटोकाल में बराबर नहीं थे। इन विशिष्ट अतिथियों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर भी शामिल थे। गोर को शाह के मंत्रिमंडल के सदस्यों से ही मिलकर लौटना पड़ा। वहीं मीडिया में आई खबरों की मानें तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का नेपाल दौरा नई दिल्ली ने इसी कारण स्थगित कर दिया, क्योंकि शाह से भेंट का कार्यक्रम नहीं बन पाया, जिसके पीछे भी प्रोटोकाल वाली परंपरा को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन निर्णयों का नेपाली मीडिया और राजनीतिक विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है, लेकिन शाह के दृष्टिकोण से देखें तो वे वही कर रहे हैं, जिसका वादा उन्होंने सत्ता में आने से पहले किया था। वह दर्शाना चाहते हैं पिछली सरकारें वादे तो करती रहीं, पर अमल नहीं कर पाईं, विशेषकर विदेशी दबाव से निपटने में और विदेश नीति को निष्पक्ष रखने में। चूंकि उन्हें प्रधानमंत्री बने दो महीने ही हुए हैं, इसलिए शाह चाहेंगे कि विदेश नीति के स्तर पर कोई ऐसा कदम न उठाएं, जिससे किसी एक देश विशेष के प्रति उनका झुकाव दिखाई दे। इसी के चलते प्रधानमंत्री ने विदेशी राजनयिकों के साथ अप्रैल में एक बैठक की, जिसमें भारत और चीन समेत पंद्रह अन्य देशों के राजदूत भी शामिल

थे। यह पहला अवसर था जब किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने ऐसा कदम उठाया हो और पड़ोसी देशों जैसे भारत या चीन के राजदूतों से निजी स्तर पर भेंट न की हो। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री शाह नीतिगत बदलावों की दिशा में ऐसे कदम उठा रहे हैं। एक ओर जहां वह विदेशी सक्रियता के मोर्चे पर नए प्रोटोकाल बना रहे हैं तो स्थापित घरेलू प्रोटोकाल की परंपरा को भी तोड़ रहे हैं। बीते दिनों जब नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे तो शाह ने बहिर्गमन किया जो प्रोटोकाल के हिसाब से बहुत खराब उदाहरण रहा। इसकी चर्चा नेपाली मीडिया में भी हुई। यह बात सही है कि हर सरकार को अपनी नीतियों और नियमों में बदलाव लाने का अधिकार है, लेकिन शाह का रवैया यही जाहिर करता है कि उनका जोर वैसे कदम उठाने पर ही अधिक है, जो उन्हें अलग तरह के नेता की छवि प्रदान करे। विदेश नीति और कूटनीति के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक ऐसी शुरुआत है, जिसका खामियाजा निकट भविष्य में नेपाल को जरूर भुगतना पड़ सकता है। यह न भूला जाए कि नेपाल भारत और चीन से घिरा हुआ देश है और तमाम मामलों में वह भारत जैसे देश पर अपनी आर्थिक और व्यापारिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से निर्भर है। इतिहास भी साक्षी रहा है कि नेपाल पर जब भी कोई संकट आया है, तब भारत एक मित्र राष्ट्र के चलते प्रथम मददगार की तरह खड़ा रहा है। ऐसे किसी साझेदार को लेकर अगर नेपाल की सरकार प्रोटोकाल की दुहाई देना शुरू करेगी तो संभव है कि कोई सहायता मांगने पर दूसरा पक्ष भी इसकी आड़ ले। नेपाल के नीति-नियंता यह भी न भूलें कि विशेष दूत हमेशा अपनी सरकार के हितैषी और नेता के संदेशवाहक होते हैं जो दोनों पक्षों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनसे मेल-मुलाकात को उपेक्षित करना संकीर्ण नीति ही कही जाएगी। इस संदर्भ में नेपाल सरकार की यही दलील है कि प्रधानमंत्री ने विदेशी प्रतिनिधियों से संवाद के लिए एक अलग व्यवस्था की है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था अमल में आ पाती है तो बेहतर होगा। इससे विदेशी संबंधों में समन्वय बनाए रखने में सहायता मिलेगी। चूंकि अभी नई सरकार को सत्ता संभाले हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे और स्पष्टता सामने आएगी, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ सवाल जरूर उठे हैं। नेपाल जिस तरह विदेशी सहायता पर निर्भर है, उसे देखते हुए इन सवालों का जल्द से जल्द उचित जवाब तलाशना उसके लिए बेहद जरूरी होगा। उसे समझना होगा कि जब कोई आग्रह दुराग्रह में परिवर्तन हो जाता है तो वह आत्मघाती भी हो सकता है।

(लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

डायनासोर की भुजाओं का अनसुलझा रहस्य, आश्चर्य और जिज्ञासा

बेहद खतरनाक डायनासोरों में से एक, टायरेनोसौरस रेक्स से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य उसकी छोटी भुजाएं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टी. रेक्स, जिसका अर्थ होता है 'जालिम छिपकलियों का राजा', एक बेहद खतरनाक शिकारी था। टी. रेक्स सफल शिकारी साबित हुआ और लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करता रहा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि टी. रेक्स अपनी बांहों का उपयोग शिकार को पकड़ने या हमला करने में करता होगा। धरती पर कभी घूमने वाले सबसे प्रसिद्ध डायनासोरों में से एक, टायरेनोसौरस रेक्स ने लोगों के मन में हमेशा से आश्चर्य और जिज्ञासा पैदा की है। 1900 के शुरुआती वर्षों में जब इसका पहला कंकाल खोजा गया, तब से ही इसने लोगों के मन में हैरानी भर दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टी. रेक्स, जिसका अर्थ होता है 'जालिम छिपकलियों का राजा', एक बेहद खतरनाक शिकारी था। इसकी लंबाई लगभग 40 से 45 फीट तक और ऊंचाई करीब 20 फीट तक होती थी। इसका वजन एक अफ्रीकी हाथी जितना भारी था और इसके दांत लगभग एक फुट लंबे होते थे। टी. रेक्स से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य उसकी छोटी भुजाएं हैं। इतना विशाल और शक्तिशाली शिकारी होने के बावजूद उसकी बांहें केवल लगभग 3 फीट लंबी थीं। यदि इन्सानों का शरीर भी टी. रेक्स जैसा होता, तो 6 फीट लंबे व्यक्ति के हाथ केवल 10 से 12 इंच के होते। आखिर इन छोटी बांहों का उपयोग क्या था? दरअसल, टी. रेक्स अकेला ऐसा डायनासोर नहीं था, जिसकी भुजाएं छोटी थीं। थेरोपोड नामक मांसाहारी डायनासोरों के समूह में कई प्रजातियों में यह विशेषता विकसित हुई थी। जीवाश्मों से पता चलता है कि टी. रेक्स के पुराने रिश्तेदारों की बांहें अपेक्षाकृत लंबी थीं, जो समय के साथ छोटी होती चली गईं। इसके बावजूद टी. रेक्स एक बेहद सफल शिकारी साबित हुआ और लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करता रहा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि टी. रेक्स अपनी बांहों का उपयोग शिकार को पकड़ने या हमला करने में करता होगा। लेकिन इसके विशाल जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि शिकार तक पहुंचने के लिए हाथों की खास जरूरत नहीं पड़ती होगी। शोध बताते हैं कि कई थेरोपोड डायनासोरों में बड़ी खोपड़ी और छोटे हाथों के बीच गहरा संबंध था। संभव है कि बड़ा सिर शिकार करने में अधिक उपयोगी साबित हुआ हो और शरीर के संतुलन के लिए हाथ छोटे होते चले गए हों। फिलहाल वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं जानते कि टी. रेक्स अपने हाथों का उपयोग कैसे करता था या वे इतने छोटे क्यों विकसित हुए। लेकिन जैसे-जैसे नए जीवाश्म मिलते रहेंगे, वैज्ञानिक नई परिकल्पनाओं की जांच करते रहेंगे और शायद भविष्य में कोई नई खोज इस रहस्य को सुलझा दे। यही विज्ञान की सबसे रोमांचक बात है, हर नई खोज हमें अतीत के किसी अनसुलझे रहस्य के और करीब ले जाती है। -द कन्वर्सेशन

वैश्विक थपेड़ों से जूझता रुपया

शिवकांत शर्मा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले देशवासियों से ऊर्जा की किफायत करने की अपील की और फिर चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। उनके वक्तव्यों के पीछे चार चिंताएं काम कर रही थीं। होर्मुज जलमार्ग बंद होने से तेल, गैस और खाद के दाम डेढ़ गुना से अधिक हो गए जिसके कारण भारत का ऊर्जा और खाद आयात बिल लगभग डेढ़ गुना हो गया है। ऊर्जा और खाद के दाम बढ़ने से देश में महंगाई बढ़ने और बजट गड़बड़ाने का खतरा पैदा हो गया है। विदेशी निवेशक पिछले दो साल से भारत से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के आसार से इसकी रफ्तार और तेज हो सकती है। ऊर्जा और खाद के आयात का बिल बढ़ने और विदेशी पूंजी के पलायन से रुपया सस्ता हो रहा है, जिसकी वजह से आयात महंगे होते जा रहे हैं। डालर की तुलना में रुपया दशकों से गिर रहा है जिसकी रफ्तार पिछले दशक में और बढ़ी है और वह 66 से गिरकर 96 पर जा पहुंचा है। इसमें से 6.1 प्रतिशत की गिरावट ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से हुई है। रुपया डालर की तुलना में ही नहीं, बल्कि जापानी येन को छोड़कर लगभग हर हार्ड करेंसी की तुलना में कमजोर पड़ा है। पिछले साल भर में तो वह पाकिस्तानी रुपये और बांग्लादेशी टके की तुलना में भी 10 प्रतिशत से अधिक गिरा, जिसकी वजह से भारत में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पाकिस्तानी रुपये का ग्राफ देखें तो उसका भाव 2016 से 2024 के बीच डालर की तुलना में भारतीय रुपये से दोगुनी रफ्तार के साथ गिरा है। 2022 से 2024 के बीच बांग्लादेशी टके की भी यही हालत हुई। 2024 के बाद पाकिस्तानी रुपये और बांग्लादेशी टके की दरों में तो थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन भारतीय रुपये के गिरने की रफ्तार कहीं तेज रही। रुपये की तुलना में इन दोनों मुद्राओं की कीमत में थोड़ा सुधार दिखाई देने की असली वजह यही है। हकीकत यही है कि मुद्रा की विनिमय दर किसी देश की अर्थव्यवस्था की ताकत या कमजोरी का पैमाना नहीं होती। मिसाल के तौर पर जापानी येन का भाव इस समय लगभग 60 पैसे है। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था जापान से डेढ़ गुना मजबूत मान ली जाए? इसी तरह यूरो आने से पहले 1998 में एक रुपया 40 इतालवी लीरा का होता था। तो क्या भारत इटली से चालीस गुना विकसित था? किसी देश की मुद्रा की कीमत उसकी जीडीपी और जारी मुद्रा की संख्या के आधार पर तय होती है और विनिमय दर मुद्रा की मांग के आधार पर चढ़ती-गिरती है। जिस देश का निर्यात आयात से अधिक होता है और जिसकी मुद्रा को लोग निवेश के लिए जमा रखना चाहते हैं, उसकी मांग बढ़ती है। परिणामस्वरूप उसकी विनिमय दर भी बढ़ती है। हालात इसके उलट होने पर मुद्रा की मांग घटती है और विनिमय दर भी गिर जाती है। इसलिए न तो मुद्रा झंडे की तरह देश की आन होती है और न ही उसकी अर्थव्यवस्था का पैमाना। भारत में सकल एफडीआइ या विदेशी निवेश की मात्रा में कमी नहीं आ रही। वह लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत से वापस जाने वाले विदेशी निवेश की मात्रा भी पिछले तीन सालों से बढ़ रही है। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो विदेशी निवेशक उन बाजारों का रुख कर रहे हैं जहां एआइ, सेमीकंडक्टर और डाटा के क्षेत्रों में नए आविष्कार हो रहे हैं। इन कंपनियों के दाम डाट-काम के दिनों की तरह हफ्तों के भीतर दोगुने-तिगुने होते जा रहे हैं। हालांकि बड़े विदेशी निवेशकों के लिए अपना निवेश एक साथ बेचना आसान नहीं होता, क्योंकि बेचने की भनक पड़ते ही दाम और मुनाफा गिरने लगता है।विडंबना इस बात की है कि उनकी यह मुश्किल भारत में लोकप्रिय हुए म्यूचुअल फंडों ने आसान की है। अमेरिकी निवेश बैंक जेफरीज का कहना है कि म्यूचुअल फंडों के जरिये निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों की मांग की आड़ में विदेशी निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार में गिरावट लाए बिना निकाल कर वहां लगा रहे हैं, जहां एक महीने में उतना मुनाफा मिल रहा है जो भारत में एक साल में नहीं मिलता।

पीड़ित को न्याय और पात्र को योजनाओं का लाभ सरकार की प्राथमिकता-केशव

जनता दर्शन,डिप्टी सीएम ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिये समाधान के निर्देश

लखनऊ (यूएनएस)। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप कार्यालय 7-कालिदास मार्ग लखनऊ में 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में प्रदेश के जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित, प्रभावी एवं संतोषजनक निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।जनता दर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन एवं युवा उपस्थित रहे। लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी समस्याएं उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। श्री मौर्य ने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं।आवश्यकतानुसार अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा पीड़ितों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराएं।'जनता दर्शन' सरकार और आमजन के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है, जिससे वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है और उनका त्वरित समाधान संभव हो पाता है। प्रदेश सरकार जनहित, सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है तथा हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई फरियादी निराश नहीं लौटेगा और प्रत्येक समस्या का हरसंभव समाधान किया जाएगा।उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न रहेबल्कि ऐसा समाधान किया जाए, जिससे पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो तथा उसे बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। भूमि विवाद एवं अवैध कब्जा सम्बंधी मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर भेजकर निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। उत्पीड़न एवं अवैध कब्जों के मामलों में आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी की जाए।मथुरा की राजकुमारी,जौनपुर के सुरेश चन्द्र मिश्रा व इटावा के सुधीर सिंह के जमीनी विवाद के सम्बन्ध मे उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियो को निर्देश दिये कि वह राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजकर समस्या का समाधान करायें। शाहजहांपुर के नीरज ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत आवास दिलाने का अनुरोध किया, बहराइच की विट्ठा ने चकबन्दी से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। लखनऊ के राम बहादुर अग्निहोत्री ने कैन्सर से पीड़ित अपनी पुत्री के इलाज हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिलाने का अनुरोध किया। मैनपुरी के अरविंद कुमार, सम्भल की रोनवती, चन्दौली के शिवाजी मौर्य, हापुड़ के आनन्द सैनी, औरैया के कृष्णदेव व कानपुर देहात के गंगाराम ने समस्यायें रखी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान समयबद्ध पारदर्शी एवं जवाबदेही के साथ होना चाहिए ताकि आमजन का शासन और प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।कई जिलों के डीएम व पुलिस अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की व समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये।

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत

लखनऊ (यूएनएस)। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के भुलभुला खेड़ा गांव में रविवार देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति शव को लेकर मलिहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतका की शादी एक साल पहले हुई थी। पति और पत्नी दोनों में अक्सर विवाद होता था। मृतका की पहचान 22 वर्षीय रूपांशी यादव पत्नी सुधीर यादव के रूप में हुई है। उसका शव रविवार रात करीब 1.25 बजे सीएचसी मलिहाबाद लाया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की। इस दौरान, मृतका के मायके पक्ष के लगभग 30 से 40 लोग अस्पताल पहुंच गए और घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर लोगों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में रखा। पुलिस ने पंचायतनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रूपांशी की शादी करीब एक वर्ष पहले हुई थी और पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

सभासद मो0 शोएब ने नगरवासियों को वितरण किया रसगुल्ला

प्रयागराज। आगामी पर्व ईद उल अजहा के अवसर पर चर्चित सभासद व भावी चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद शोएब नगर पंचायत लालगोपालगंज प्रयागराज ने आगामी पर्व ईद-उल-अजहा के अवसर पर सभी नगरवासियों को आगामी ईद उल अजहा तहे दिल से दिली मुबारकबाद दी। इस दौरान भावी चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद शोएब ने लोगों को हर वार्ड में रसगुल्ले बांटे, जिससे क्षेत्र में गंगा-जम्मुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली । भाईचारे और सौहार्द के त्योहार ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश की गंगा-जमुनी तहजीब की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ भावी चेयरमैन प्रत्याशी शोएब ने खुद आगे बढ़कर लोगों में न सिर्फ ईद की खुशियां बांटी, बल्कि रसगुल्लों के साथ मिठास भी घोली।' भावी चेयरमैन प्रत्याशी का यह अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया। इस मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि त्योहारों पर इस तरह से रसगुल्ले बांटने से समाज में प्रेम और आपसी सौहार्द को भी मजबूत करता है लोगों ने एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और अमन-चैन की दुआ मॉंगी वही भावी चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद शोएब ने अपने शायराने अंदाज में कहा कि' है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना , चाहे होली हो या ईद, य फिर दीपावली हर त्योहार को मिल-जुल कर मनाने की यही परंपरा हमारे देश की असली ताकत है इस हम सबको जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर इसे बनाकर रखना होगा यही हमारी असली पूँजी है । ईश्वर ने अगर आपकी देने लायक बनाया है तो जरूर हमे सबकी मदद करनी चाहिए यही हमारा लक्ष्य है कि हमारे नगर पंचायत के लोग हर त्यौहार को बिना भेदभाव के मिलजुल कर मनाये।

न्यू स्टैण्डर्ड पब्लिक स्कूल त्रिपुला में आयोजित हुई अभिभावक-शिक्षक बैठक

रायबरेली। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुला में विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास, अनुशासन, सर्वांगीण प्रगति एवं विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) का आयोजन किया गया। बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं शिक्षकों के मध्य आयोजित बैठक में अभिभावकों ने सहभागिता करते हुए अपने बच्चों के पीरियाडिक एग्जाम-1 के परिणाम, शैक्षिक प्रदर्शन एवं प्रगति पर शिक्षकों से विस्तार से चर्चा की। शिक्षकों ने विद्यार्थियों की पढ़ाई को और प्रभावी बनाने, नियमित अभ्यास तथा बेहतर परीक्षा तैयारी के लिए आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया। प्रधानाचार्य शिवलखन प्रजापति ने कहा कि 'बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तभी रखी जा सकती है।जब अभिभावक और शिक्षक एक समान उद्देश्य एवं सकारात्मक सोच के साथ मिलकर कार्य करें। विद्यालय और परिवार के बीच बेहतर तालमेल विद्यार्थियों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।' उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की नियमित पढ़ाई, अनुशासन एवं मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। इस अवसर पर फैजान खान, शिवकरन पाल, संचिता त्रिवेदी, प्रशांत पांडेय, शुभी सिंह, शाहीन खान, अजय सिंह, गिरीश श्रीवास्तव सहित शिक्षक / शिक्षिकाएँ, अभिभावक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे।

यूपी में बिजली संकट पर भड़के अखिलेश यादव, विधायकों की चिट्ठी को बताया टिकट का आवेदन

लखनऊ (यूएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उप्र में असहनीय महा विद्युत आपदा की वजह से लगातार बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए भयभीत भाजपाई विधायक-सांसद दिखावटी चिट्ठी का कागजी कवच बना रहे हैं। यादव ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह चिट्ठी दरअसल अपनी सरकार को लिखा कोई जन हित का पत्र नहीं है, बल्कि भाजपा रूपी डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनावों में टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र है। उन्होंने साफ किया कि हमारे गठबंधन में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, जो जनता को दुख-दर्द और दिक्कतों के सिवा कुछ नहीं देते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि इस जानलेवा गर्मी में परिवारों में बड़े बुजुर्गों, बीमारों, बच्चों और खाने-पानी की व्यवस्था में झुलसती महिलाओं की क्या दुर्दशा हो रही है, ये केवल परिवारवाले ही समझ सकते हैं। कभी आपदा में अवसर ढूंढने वालों ने, अवसर की जगह जिस अफसर को ढूंढा था, वो अफसर अब स्वयं आपदा साबित हो रहा है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि समस्या का समाधान पूछने पर दोनों हाथ खड़ा करके नारा लगाकर बच निकलने वालों के रहते समस्या नहीं सुलझेगी। उन्होंने कहा कि किसी के लिए ये बड़ा मौका है कि वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके किसी दूत-मंत्री को हटा दे। इससे मुख्य जी को अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने और किसी एक घाटहीन को समायोजित करने का मौका भी मिल जाएगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उप्र की भाजपा सरकार भी जानती है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। इसीलिए वो जनता की मुश्किलों और मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज करके बस अपने खजाने भरने में लगी है। उन्होंने लिखा कि जन-जन कहे आज का, भार बन गई भाजपा।

कपिल देव ने की प्रशिक्षण एवं सेवायोजन स्थायी समिति के सदस्यों के साथ बैठक

'न्यू एज स्किल्स' पर विशेष फोकस, रोबोटिक्स, ईवी, सीएनसी को बढ़ावा

लखनऊ (यूएनएस)। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने सोमवार को प्रशिक्षण एवं सेवायोजन स्थायी समिति के सदस्यों के साथ विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष संख्या-58 में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन स्थायी समिति की बैठक की। बैठक में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई और सदस्यों में अपने सुझाव दिए।श्री अग्रवाल ने प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई की संख्या, प्रवेश एवं प्रशिक्षण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। सरकारी आईटीआई मे 1.29 लाख तथा निजी आईटीआई में 2.77 लाख युवाओं का प्रवेश हुआ है। वैश्विक एवं औद्योगिक मांग के अनुरूप 'न्यू एज स्किल्स' जैसे रोबोटिक्स, सीएनसी मशीनिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंप्यूटर एवं अन्य तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण को और सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। योगी सरकार के प्रयासों से टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हुए समझौते के अंतर्गत प्रदेश के 150 आईटीआई संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों एवं तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे युवाओं को उद्योगों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने में किया जा रहा है। 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के माध्यम से इंटर कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी दक्षता से भी जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में पांच 'सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड इनोवेशन' स्थापित किए जा रहे हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों से जोड़ने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा रहा है। बैठक में डॉ. वीर विक्रम सिंह प्रिन्स विधायक शाहजहांपुर मुक्ता संजीव राजा विधायक, अलीगढ़ डॉ. एमपी आर्य विधायक बरेली ओम कुमार विधायक, बिजनौर जय देवी विधायक, लखनऊ, कैलाश नाथ विधायक, बलरामपुर, डॉ. आरके वर्मा विधायक, प्रतापगढ़ एवं अशोक कुमार विधायक, रायबरेली एवं प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, विशेष सचिव अभिषेक सिंह, मिशन निदेशक पुलकित खरे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

यूपीएससी का पेपर खराब होने पर वॉइस प्रिंसिपल का बेटा गोमती में कूदा

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी लखनऊ में सरकारी इंटर कॉलेज की वॉइस प्रिंसिपल का बेटा गोमती में कूद गया। घटना आज यानी सोमवार सुबह की है। युवक प्रखर पाल को गोताखोर ढूंढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक वह नहीं मिला। मां सुष्मलता राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज में वॉइस प्रिंसिपल के पद पर तैनात हैं। बेटे के नदी में कूदने की जानकारी मिली तो वह घटनास्थल पहुंचीं। मां का घाट पर रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने रोते हुए बताया कि कल वह यूपीएससी का पेपर देने गया था। बता रहा था कि उसका पेपर खराब हो गया है। मैंने कहा था कि कोई बात नहीं बेटा। तुम अच्छे बच्चे हो। दूसरी मीटिंग का पेपर ध्यान देना। इसके बाद उससे कोई बात नहीं हुई। पिता विष्णु गोपाल पाल की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह पक्के पुल पर एक स्कूटी खड़ी मिली। कुछ देर बाद लोगों ने युवक को गोमती नदी में छलांग लगाते देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चौक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया। पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है।

किसानों की डिजिटल पहचान की ओर तेजी से बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

यूपी में अंश निर्धारण का कार्य 87.19 प्रतिशत पूरा

लखनऊ (यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से डिजिटल कृषि व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी, त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने बड़े स्तर पर परिणाम देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की सक्रिय पहल के चलते अब तक 2.28 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जो केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य का 79.10 प्रतिशत कार्य पूरा है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान प्रगति के अनुसार 2,28,36,658 किसानों का नामांकन किया जा चुका है, जबकि 60,33,837 किसानों का पंजीकरण अभी शेष है। वर्तमान प्रगति के आधार पर किसानों की आईडी निर्माण प्रक्रिया 20 अगस्त तक पूर्ण होने का अनुमान है।सरकार का उद्देश्य किसानों का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि अनुदान, ऋण सुविधा और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके। सरकार की प्राथमिकता केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं है बल्कि भूमि और किसानों के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना भी है। 'अंश निर्धारण' का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अंश निर्धारण का कार्य 87.19 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इससे भूमि रिकॉर्ड की शुद्धता बढ़ेगी और भविष्य में विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। फार्मर रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे सरकार को वास्तविक किसानों की पहचान करने, योजनाओं की मॉनिटरिंग करने और कृषि आधारित नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और डेटा आधारित योजना क्रियान्वयन के जरिए उत्तर प्रदेश को आधुनिक और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान को भी व्यापक परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जो आने वाले समय में प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

सड़क निर्माण में देरी पर भड़के लोग पीडब्लयूडी के खिलाफ प्रदर्शन

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी लखनऊ के इस्माइल गंज द्वितीय वार्ड में सड़क निर्माण में लगातार हो रही देरी को लेकर सोमवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व पार्षद रुद्र प्रताप सिंह के साथ में लोगों ने ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्लयूडी) के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने पीडब्लयूडी मुर्दाबाद और भ्रष्टाचारी होश में आओ का नारा लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। लोगों ने बताया कि एक महीने पहले स्थानीय विधायक ओपी श्रीवास्तव ने नारियल फोड़कर विधिवत पूजा की थी, लेकिन काम अभी तक नहीं शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सड़क निर्माण कार्य जल्दी शुरु नहीं हुआ तो प्रदर्शन और तेज करेंगे। प्रदर्शनकारी किशोरी लाल चौराहा से चौहान प्लाजा तथा फैजाबाद रोड से रजत डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नवंबर 2025 में दोनों सड़कों के निर्माण के लिए करीब 32-32 लाख रुपए के ई-टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन छह महीने बीतने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ये दोनों सड़कें अंदरूनी लगभग दो दर्जन मोहल्लों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग हैं, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन रहता है। सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रतीक की तेरहवीं में पत्नी अपर्णा रो पड़ीं, अखिलेश, डिंपल समेत पूरा यादव परिवार शामिल

लखनऊ (यूएनएस)। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक की आज तेरहवीं है। कार्यक्रम में पत्नी अपर्णा यादव ने पूड़ियां बांटीं। इस दौरान जब लोगों ने 'प्रतीक भैया अमर रहें' के नारे लगाए, तो वह खुद को रोक नहीं पाईं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और घर के अंदर चली गईं। सीएम योगी भी तेरहवीं में शामिल हुए। उन्होंने प्रतीक को श्रद्धांजलि दी और अपर्णा को सांत्वना दी। अखिलेश, शिवपाल यादव और डिंपल यादव समेत पूरा परिवार अपर्णा के घर पहुंचा। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी पूड़ियां बांटीं। लोकगायिका मालिनी अवस्थी भी तेरहवीं में पहुंचीं। लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित अपर्णा के घर पर कार्यक्रम हो रहा है। इसमें रामधुन बज रही है। शहर के कई इलाकों में प्रतीक की तेरहवीं से जुड़े शोक संदेशों के होर्डिंग लगाए गए हैं। 13 मई की सुबह प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। अगले दिन यानी 14 मई को लखनऊ के बैकुंठ धाम श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

सामाजिक क्रांति आंदोलन की ज्वलंत मशाल थे चंद्रजीत यादव-चंद्रभूषण सिंह यादव

संवाददाता

देवरिया। सामाजिक समता के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रजीत यादव ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने हेतु सड़क से सदन तक लड़ने का कार्य किया,उक्त उद्गार रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डुमरी स्थित सपा जन संपर्क कार्यालय पर आयोजित स्मृति दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में व्यक्त करते हुए सपा के पूर्व प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह यादव ने कहा कि चंद्रजीत यादव ने संसद के अंदर खड़े होकर बेकारी के सवाल पर कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो। सपा के पूर्व प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह यादव ने चंद्रजीत यादव को याद करते हुए कहा कि आज जो तमाम जगहों पर पुलिस फर्जी काउंटर कर रही है उस पर 1980 के दौर में अपने विचार रखा था कि ब्रिटेन में पुलिस ने एक भगोड़े कैदी की जगह पर गफलत में एक निदोष व्यक्ति का काउंटर कर दिया जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े हो क्षमा मांगा और दोषी पुलिस वाले सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे गए। वे पुलिस तंत्र को बेलगाम होने से रोकने के हिमायती थे।चंद्रजीत यादव को सामाजिक क्रांति आंदोलन की ज्वलंत मशाल बताते हुए सपा के पूर्व प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह यादव ने उनके चित्र के समक्ष नतमस्तक हो नमन किया। उक्त अवसर पर उपस्थित मुरलीधर,व्यास यादव,दयानंद यादव, अभिषेक गुड्डू गोंड, बेलभद्र गोंड, सुरेश नारायण सिंह, शीलू यादव,गोविंद यादव,शंकर गोंड, नारायण प्रसाद,नगीना यादव आदि ने स्मृतिशेष चंद्रजीत यादव को श्रद्धावनत हो नमन किया।

डीएम की अध्यक्षता में जिला गंगा और पर्यावरण समितियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

संवाददाता

रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति, वृक्षारोपण समिति और पर्यावरण समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा छोटी नदियों के पुनरोद्धार एवं कायाकल्प हेतु गठित समिति से कायर्योजना तैयार किए जाने तथा गंगा नदी में गिर रहे 37 नालो की टैपिंग के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी से समीक्षा की गई।

जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सभी चिन्हित नालों को गंगा नदी में प्रवाहित होने से रोकने हेतु फ़िल्टर चौबर बनाए जा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कोई भी नाला गंगा नदी में प्रवाहित न होने पाए। इसके संबंध में खंड स्तरीय अधिकारियों एवं वन विभाग के साथ समेकित समिति का गठन कर माहवार निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिला गंगा समिति को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। जिलाधिकारी द्वारा जल निगम (ग्रामीण) से लोन नदी के जल की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर मुख्य अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रेषित किए जाने की बात कही गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में वायु गुणवत्ता की समय-समय पर जांच कराई जाए तथा उसका प्रसारण जनपद के प्रमुख चौराहों पर स्थापित डिस्प्ले बोर्डों पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने जनपद में ई-बस संचालन हेतु सहायक परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका परिषद के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर रोडमैप तैयार करें, ताकि ई-बस का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। बैठक में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रखर मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में विगत वर्ष रोपित पौधों के लक्ष्य के सापेक्ष जीवितता प्रतिशत संतोषजनक नहीं है, जिससे जनपद की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा रोपित मृत पौधों के स्थान पर नवीन पौधे लगाकर उनकी क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूप से की जाए। बैठक में उपायुक्त श्रम (रोजगार) प्रमोद सिंह, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद रायबरेली स्वर्ण सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षण संजीव कुमार सिंह सहित जिला परियोजना अधिकारी जिला गंगा समिति रायबरेली क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रदुषण नियन्त्र बोर्ड व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

इसी क्रम में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा आंधी-तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों को रिस्टोर कर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में आंधी-तूफान के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए तथा अतिरिक्त मैनपावर लगाकर विद्युत आपूर्ति की शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विद्युत विभाग पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति बहाली के कार्यों की सतत निगरानी की जाए तथा जहां भी ट्रांसफार्मर, पोल अथवा तार क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाए। साथ ही, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विभिन्न तहसीलों में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, मरम्मत कार्यों की प्रगति एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, अधीक्षण अभियंता अविनाश पटेल, अखिलेश कुमार सहित विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता उपस्थित रहे।

मानवता और सेवा की अनुपम मिसाल बना औघड़ आश्रम का प्याऊ, लोगों की बुझा रहा प्यास

संवाददाता

रायबरेली। भीषण गर्मी, तपती धूप और उमस भरे मौसम के बीच जहां आमजन राहत की तलाश में इधर-उधर भटकते नजर आते है, वहीं औघड़ भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम द्वारा संचालित प्याऊ मानवता, सेवा और परोपकार की अद्भुत मिसाल बनकर लोगों को राहत पहुंचा रहा है। आश्रम के तत्वावधान में विगत 15 वर्षों से प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में यह सेवा कार्य अनवरत रूप से संचालित किया जा रहा है। इस प्याऊ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध एवं शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही गुड़, बताशा और पेठा वितरित कर लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाने का पुनीत कार्य किया जाता है। स्थानीय दीवानी कचहरी से कोतवाली रोड जाने वाले मार्ग पर स्थापित यह प्याऊ आज जिले में सेवा भावना, सामाजिक समर्पण और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक बन चुका है। कचहरी आने वाले वादकारी, अधिवक्ता, रिक्शा चालक, श्रमिक, व्यापारी, राहगीर और आम नागरिक यहां रुककर पानी पीते है और आश्रम की इस निःस्वार्थ सेवा की मुक्त कंठ से सराहना करते है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी शुरू होते ही उन्हें औघड़ आश्रम के प्याऊ लगने का इंतजार रहने लगता है, क्योंकि यह प्याऊ केवल पानी पिलाने का माध्यम नहीं बल्कि इंसानियत और सेवा का जीवंत संदेश है। उल्लेखनीय है कि इस सेवा कार्य की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। उस समय मुख्यालय पड़ाव, वाराणसी आश्रम से पधारे साधु मगहिया राम की गरिमामयी उपस्थिति में व्यापारी नेता मुकेश रस्तोगी के प्रतिष्ठान पर इस प्याऊ का भव्य शुभारंभ किया गया था। धीरे-धीरे यह सेवा कार्य जनमानस के दिलों में अपनी विशेष पहचान बनाता चला गया और आज यह पूरे जनपद में प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। आश्रम की इस पहल से प्रेरित होकर अब जिले के विभिन्न बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर भी सामाजिक संगठनों एवं जागरूक नागरिकों द्वारा प्याऊ लगाए जाने लगे है। धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी औघड़ भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम केवल गर्मी में प्याऊ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्था वर्षों से समाज सेवा के अनेक कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रही है। आश्रम परिसर में प्रत्येक रविवार को पथरी के रोगियों को फकीरी पद्धति से निःशुल्क दवा वितरित की जाती है। दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले लोग यहां उपचार प्राप्त कर लाभान्वित होते है। इसके अतिरिक्त समाज से उपेक्षित एवं असहाय कुष्ठ रोगियों के लिए भी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं है। समाज जिन कुष्ठ रोगियों को उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, उन्हें आश्रम न केवल आश्रय प्रदान करता है, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी उपलब्ध कराता है। आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगियों की सेवा, भोजन, चिकित्सा और देखभाल की समुचित व्यवस्था की जाती है। यही कारण है कि यह संस्था वर्षों से मानवता की सेवा में समर्पित होकर समाज के लिए प्रेरणा का केन्द्र बनी हुई है। आश्रम द्वारा केवल गर्मी में प्याऊ संचालन ही नहीं, बल्कि वर्ष भर विभिन्न सामाजिक एवं मानवीय सेवा कार्य संचालित किए जाते हैं। ठंड के मौसम में आश्रम की ओर से विशेष शिविर लगाकर जरूरतमंदों को रजाइयों का वितरण किया जाता है। इतना ही नहीं, रात के समय आश्रम के सेवादार रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को बिना किसी प्रचार-प्रसार के चुपचाप कंबल ओढ़ाने का कार्य करते है। सेवा का यह अनूठा स्वरूप लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बना चुका है और आश्रम की मानवीय संवेदनाओं को समाज में विशेष सम्मान दिलाता है। इसके साथ ही विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों के बीच फल वितरण, जरूरतमंद परिवारों को पंखा वितरण तथा धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता एवं सेवा भावना को प्रोत्साहित करने हेतु मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों एवं साधु-संतों की पीठों में झाड़ू वितरण जैसे कार्य भी निरंतर किए जाते हैं।

राष्ट्रपति भवन में उत्तर प्रदेश की सात विभूतियां पद्म सम्मान से सम्मानित, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान

राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित भव्य नागरिक अलंकरण समारोह में भारत की राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश से संबंधित सात प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। कला, खेल, पुरातत्व, चिकित्सा, विज्ञान तथा आयुर्वेद जैसे विविध क्षेत्रों में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म विभूषण और पद्म श्री से अलंकृत किया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात वायलिन वादक डॉ. (श्रीमती) एन. राजम् को कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 'सिंगिंग वायलिन' के नाम से विख्यात डॉ. राजम् ने वायलिन पर हिंदुस्तानी गायन शैली को प्रस्तुत करने वाली 'गायकी अंग' तकनीक को विकसित कर शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन के रूप में उन्होंने दशकों तक संगीत शिक्षा को समृद्ध किया तथा देश-विदेश में भारतीय संगीत की विशिष्ट पहचान स्थापित की। खेल के क्षेत्र में पैरा हाई जंपर श्री प्रवीण कुमार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। विश्व नंबर-1 पैरा हाई जंपर के रूप में पहचान बना चुके प्रवीण कुमार पैरालंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं। टोक्यो पैरालंपिक में रजत और पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने कई एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं तथा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रो. बुद्ध रश्मि मणि को पद्म श्री प्रदान किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संग्रहालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने अयोध्या, सारनाथ, कपिलवस्तु और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन का नेतृत्व किया। अयोध्या उत्खनन से जुड़े उनके शोध कार्यों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। उन्होंने लगभग 200 पुरातात्विक स्थलों की खोज की तथा भारतीय इतिहास और विरासत अध्ययन को नई दिशा दी। चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रो. (डॉ.) राजेंद्र प्रसाद को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। पल्मोनरी मेडिसिन और तपेदिक उन्मूलन के क्षेत्र में उन्हें वैश्विक विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने केजीएमयू, लखनऊ में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज आधारित डीओटीएस केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका मॉडल बाद में देशभर के सैकड़ों मेडिकल कॉलेजों में अपनाया गया। 'पल्मोनरी मेडिसिन के जनक' के रूप में विख्यात प्रो. प्रसाद ने टीबी और श्वसन रोगों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। कृषि अनुसंधान एवं विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए डॉ. अशोक कुमार सिंह को पद्म श्री प्रदान किया गया। उन्होंने बासमती धान की उन्नत, जलवायु-अनुकूल तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में विकसित पूसा बासमती की विभिन्न किस्मों ने भारत के बासमती निर्यात और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान ने भारतीय कृषि को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। संक्रामक रोगों, विशेषकर काला-अजार के उपचार एवं अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रो. श्याम सुन्दर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने काला-अजार के त्वरित निदान और प्रभावी उपचार पद्धतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शोध कार्यों के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नई उपचार पद्धतियों को अपनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनके नेतृत्व में काला-अजार अनुसंधान को वैश्विक पहचान मिली है।आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. केवल कृष्ण ठकराल को पद्म श्री प्रदान किया गया। उन्होंने 'क्षार सूत्र' चिकित्सा पद्धति तथा 'कर्मवेधन' जैसी आयुर्वेदिक शल्य प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाकर आयुर्वेदिक सर्जरी को व्यापक स्वीकार्यता दिलाई। आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अनेक शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की इन सात विभूतियों को प्राप्त यह सम्मान राज्य के लिए गर्व का विषय है। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं तथा राष्ट्र निर्माण में समर्पित योगदान की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत करती हैं।

अंडरपास की मांग को लेकर सालखपुर में ग्रामीणों का प्रदर्शन, रेलवे कार्य रोकने की चेतावनी

जौनपुर। जनपद के सालखपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में चल रहे रेलवे निर्माण कार्य के विरोध में रविवार को ग्रामीणों और युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने रेलवे ट्रैक के पास एकत्र होकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि 'जब तक अंडरपास नहीं, तब तक रेलवे का काम नहीं।' प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो रेलवे का कार्य नहीं होने दिया जाएगा।प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि रेलवे लाइन के दोनों ओर बसे गांवों के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मांग करने के बावजूद अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है।ग्रामीणों ने बताया कि वे पूर्व में सांसद और जिलाधिकारी से मिल चुके हैं। इसके अलावा डीआरएम लखनऊ को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन मामला फाइलों में दबकर रह गया और धरातल पर कोई कार्य नहीं दिखा। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन और रेलवे विभाग की अनदेखी से मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।प्रदर्शन के दौरान लोगों ने 'जन-जन की यही पुकार, अंडरपास जरूरी है' तथा 'सालखपुर की यही पुकार, अंडरपास जरूरी है' जैसे नारे लगाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक अंडरपास निर्माण की घोषणा और कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा, बुजुर्गों के साथ क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे।

लापता युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला, गांव में सनसनी

रामपुर, जौनपुर। जौनपुर जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धनुआ में एक 18 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव से लगभग 200 मीटर दूर स्थित एक सुनसान कुएं में उतराया हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाकर कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनुआ गांव निवासी राधेश्याम सरोज की 18 वर्षीय पुत्री निधि सरोज बीते 22 मई शुक्रवार की सुबह लगभग 5 बजे घर से निकली थी, जिसके बाद वह अचानक लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब युवती का कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने रामपुर थाने में गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि रविवार सुबह गांव के कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव से लगभग 200 मीटर दूर एक सुनसान स्थान पर स्थित पुराने कुएं में युवती का शव उतराया हुआ दिखाई दिया। शव दिखाई देने की सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों द्वारा तत्काल इसकी सूचना रामपुर पुलिस को दी गई।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

निर्माण कार्य रोकने को लेकर मारपीट, पांच पर केस दर्ज

बरसठी, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के पाली गांव में जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है। उक्त गांव निवासी प्रमिला देवी पत्नी संजय सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि वह अपनी जमीन पर बाउंड्री का निर्माण कार्य करा रही थीं। इसी दौरान गांव के ही चंद्रभान सिंह, अनुज सिंह, कुसुम सिंह, ममता सिंह तथा तृप्ति सिंह ने निर्माण कार्य जबरजस्ती रोक दिया। आरोप है कि 10 मई की सुबह करीब नौ बजे सभी लोग एकजुट होकर मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन दीवार को गिराने लगे। विरोध करने पर प्रमिला देवी, उनके पति संजय सिंह तथा पुत्री श्वेता सिंह के साथ मारपीट की गई, जिससे तीनों घायल हो गए। पीड़िता ने बताया कि मामले को लेकर पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिस पर थाने में समझौता कराया गया था। इसके बावजूद दोबारा घटना होने पर पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर तहरीर दी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सीय परीक्षण कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 191(2), 115(2) और 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाई में जुटी है।

थाना समाधान दिवस में डीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, कई मामलों का मौके पर निस्तारण

जौनपुर। डीएम ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर में जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया।जनसुनवाई के दौरान रासमंडल निवासी राहुल राय पुत्र रमेश राय के पड़ोसी से प्लास्टर कराने को लेकर चल रहे विवाद तथा प्रियंका श्रीवास्तव पुत्री आशीष के ताला खुलवाने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल समाधान कराया।वहीं जितेंद्र कुमार, पुष्पेंद्र पाल तथा तारतला निवासी अशोक कुमार जायसवाल एवं अनुराग गुप्ता के प्रार्थना पत्र संबंधित एसएचओ को हस्तांतरित करते हुए निर्देश दिया गया कि मौके पर पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण ढंग से मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। भूमि विवाद एवं राजस्व संबंधी मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर जांच करे तथा पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को त्वरित न्याय मिल सके।इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आयुष श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह, एसएचओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम ने कृषि भवन स्थित गौशाला का किया औचक निरीक्षण

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. के द्वारा शनिवार देर सायं कृषि भवन स्थित गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने भीषण गर्मी के दृष्टिगत गौशाला में पशुओं के लिए शेड, भूसा, हरा चारा एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौशाला में पानी, भूसा एवं हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिए। तथा गौशाला में नियमित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए पशु चिकित्साधिकारी को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, उपजिलाधिकारी संतवीर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पवन कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारीगण एवं गौशाला के केयरटेकर उपस्थित रहे।

बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार मजदूरों को रौंदा, एक की मौत

जौनपुर। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के उसरा बाजार पावर हाउस के पास रविवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार दो मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच-731 हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे काफी देर तक यातायात बाधित रहा। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। मृतक की पहचान पट्टी दयाल गांव निवासी चंचल उर्फ पट्टू के रूप में हुई है। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल विनोद उर्फ नारद को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार स्कॉर्पियो UP 65 CE 4855 वाराणसी की तरफ जा रही थी की अनियंत्रित होकर बाइक सवार मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा स्कॉर्पियो चालक की तलाश शुरू कर दी है।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला वृक्षारोपण एवं गंगा समिति की बैठक सम्पन्न

प्रभात उजाला ब्यूरो

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में शनिवार देर सायं जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित दिये गये कि 30 मई 2026 तक गड्ढा खुदान का कार्य पूर्ण कर लिया जाये तथा ब्लाक स्तर पर वृक्षारोपण की तैयारियों हेतु समस्त ब्लाकों पर एक कार्यशाला आयोजित किया जाये। वर्ष 2026 वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान में वन विभाग व अन्य विभागों को निर्देशित दिये गये कि वृक्षारोपण महायज्ञ को सफल बनाने हेतु अपने-अपने क्षेत्रों के मा0 सांसद / विधायक/ एम0एल0सी/जन प्रतिनिधिगण से सम्पर्क पौधरोपण करकर वृक्षारोपण का प्रारम्भ किया जाये, तथा समस्त अन्य विभागों को निर्देशित दिये गये कि पौधरोपण स्थलों का मिट्टी की जॉच अवश्य करा ले मिट्टी की पी0एच0 मानक के अनुसार प्रजातियों के पौधो का रोपण किया जाये। एक स्थल पर कम से कम 1500 से 2000 पौधों का रोपण किया जाये एवं पौधों की सुरक्षा हेतु तार बाड लगानें हेतु निर्देशित दिये गये जिससे पौधों का जीवित रख जा सकता है। गौशालाओं पर छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, परियोजना निदेशक के0 के0 पांडे, डीएफओ प्रमिला, डीडीओ सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

जिलाधिकारी ने रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में रविवार को एनआईसी सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।बैठक जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त हुई विद्युत आपूर्ति की समस्यायों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था की जानकारी ली जिस पर लोकेश कुमार- अधीक्षण अभियंता विद्युत यमुनापार के द्वारा बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल है। रात्रि में बिजली की मांग बढ़ जाने के कारण रोस्टिंग की जा रही है और रात्रि की कटौती को दिन में कोम्पन्सेट कर ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत सप्लाई दी जा रही है । ओवरलोडिंग से बचाव हेतु अवैध कटिया कनेक्शन हटाने के लिए पीक ऑवर में विभागीय टीम और विजिलेंस टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग और काम्बिंग की जा रही हैं। बताया कि सभी उपकेंद्रों पर मानक के अनुसार कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

प्रयागराज मे जमीनी विवाद में भाई ने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर की हत्या

प्रयागराज। गंगानगर मऊआइमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कहली बादलपुर गांव में जमीन बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने अपने दूसरे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने गुस्से में आकर छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।हमले में गंभीर रूप से घायल भाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मऊआइमा थाना प्रभारी निरीक्षक राम मूर्ति यादव ने बताया की तीनो भाइयों मे जमीन का विवाद चल रहा था। जमीन के विवाद में ही यह घटना क्रम हुआ है। फिलहाल शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

लेखपाल से अभद्रता, पिता-पुत्र पर केस

बरसठी, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के हरद्वारी गांव में तैनात लेखपाल के साथ अभद्रता, जातिसूचक टिप्पणी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं समेत एससी-एसटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच सीओ मड़ियाहूं को सौंपी गई है। राजस्व हल्का संख्या 536 में तैनात लेखपाल सुरेंद्र कुमार की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार, वह 21 मई को ग्राम सभा से संबंधित पत्थरगड्डी का कार्य कर वापस लौट रहे थे। आरोप है कि हरद्वारी गांव में राजमणि पटेल की दुकान के पास गांव निवासी अरविंद मोहन उर्फ लल्ला तिवारी अपने पुत्र मयंक के साथ बाइक से पहुंचे और उनकी मोटरसाइकिल रोक दी।लेखपाल का आरोप है कि दोनों ने उनका हाथ मोड़कर भद्दी गालियां दीं और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित लेखपाल ने बताया कि सड़क पर पड़ी ईंट उठाकर मारने का प्रयास किया गया। आरोप है कि सरकारी कागजात छीनने की कोशिश में गांव का नक्शा फाड़कर फेंक दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित अरविंद मोहन उर्फ लल्ला तिवारी व उनके पुत्र मयंक के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धारा 115(2), 352, 351(3), 324(4), 132 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(नं) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है। थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

छोटे किसान से प्रगतिशील कृषक बनने तक की प्रेरणादायक सफलता की कहानी

छोटी जोत से बड़ी सफलताः बृजेश कुमार पटेल बने प्रगतिशील किसान

हाइटेक नर्सरी और उद्यान विभाग के सहयोग से किसान बन रहे आत्मनिर्भर

कम जमीन, नई सोच और आधुनिक खेती से बृजेश कुमार पटेल बने मिसाल

जौनपुर।जनपद के विकास खण्ड जलालपुर अंतर्गत ग्राम आदत शाहपुर कलान निवासी किसान बृजेश कुमार पटेल ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि किसान आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच और विभागीय सहयोग के साथ खेती करे, तो कम भूमि से भी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। सीमित संसाधनों और छोटी जोत के बावजूद उन्होंने उद्यानिकी खेती अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है और आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।कृषक का परिचय - प्रगतिशील किसान बृजेश कुमार पटेल इंटरमीडिएट शिक्षित हैं तथा उनके पास कुल 0.506 हेक्टेयर कृषि भूमि है। पहले वे परंपरागत रूप से धान एवं गेहूँ की खेती करते थे, जिससे सीमित आय ही प्राप्त हो पाती थी। खेती में बढ़ती लागत और घटती आमदनी उनके सामने बड़ी चुनौती थी।शुरुआती संघर्ष और चुनौतियाँ - बृजेश कुमार पटेल ने बताया कि खेती के शुरुआती दौर में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था और आधुनिक तकनीकी जानकारी का अभाव था। कम भूमि होने के कारण यह समझना कठिन था कि ऐसी कौन-सी फसल उगाई जाए जिससे पूरे वर्ष परिवार की आजीविका सुचारु रूप से चल सके। पारंपरिक बीज और खाद के प्रयोग से लागत बढ़ती जा रही थी जबकि उत्पादन अपेक्षाकृत कम मिल रहा था।बदलाव का टर्निंग प्वाइंट - उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में उद्यान विभाग से संपर्क किया। जिला उद्यान अधिकारी श्रीमती सीमा सिंह राणा द्वारा संचालित हाइटेक नर्सरी एवं उन्नत बीज वितरण योजनाओं की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाया। विभागीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग से उन्हें यह समझ आया कि खेती केवल परंपरागत कार्य नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रबंधन का माध्यम है। हाइटेक नर्सरी से प्राप्त उन्नत पौधों एवं प्रशिक्षण ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्होंने भिंडी की व्यावसायिक खेती करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने कद्दू, टमाटर, करेला एवं बैंगन जैसी संकर शाकभाजी फसलों की खेती भी प्रारंभ की। आधुनिक तकनीक से मिली सफलता - बृजेश कुमार पटेल ने बताया कि भिंडी की खेती में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया।

हाइटेक नर्सरी से प्राप्त स्वस्थ पौधों का प्रयोग किया, बेड बनाकर रोपाई की तथा वैज्ञानिक खरपतवार नियंत्रण तकनीक अपनाई और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखकर खेती की। मात्र 10 बिस्वा भूमि पर लगभग रू. 8,000 की लागत लगाकर उन्होंने 60 दिनों में लगभग रू. 60,000 का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्तमान में भी भिंडी की तुड़ाई से उन्हें लगभग रू. 20,000 अतिरिक्त शुद्ध लाभ मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हाइटेक नर्सरी कृषि विज्ञान केन्द्र बक्शा से प्राप्त कद्दू, टमाटर, करेला एवं बैंगन के पौधों की खेती से उन्हें लगभग रू. 20,000 का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ। बृजेश कुमार पटेल ने बताया कि खेती में सफलता के लिए बड़ी जमीन नहीं, बल्कि नई सोच और सही तकनीक की आवश्यकता होती है। सीमित भूमि से लगभग रू. 1 लाख तक का लाभ अर्जित किया। अन्य किसानों के लिए संदेश - बृजेश कुमार पटेल अन्य किसानों को संदेश देते हुए कहते हैं कि किसानों को परंपरागत फसलों के सीमित दायरे से बाहर निकलकर तकनीकी एवं वैज्ञानिक खेती अपनानी चाहिए। यदि किसान विभागीय योजनाओं, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों का सही उपयोग करें, तो कम भूमि से भी बेहतर उत्पादन और अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपनी सफलता के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन, उद्यान विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र बक्शा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं और विभागीय मार्गदर्शन से ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि यदि किसान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेकर आधुनिक खेती अपनाएं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है।

स्वदेश भारत न्यूज
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक स्वदीश कुमार द्वारा स्वदेश भारत पब्लिकेशन ग्राम कनकपुर पोस्ट फतेहगंज जिला जौनपुर (उ०प्र०) 222132 से मुद्रित एंव प्रकाशित ।
सम्पादक
स्वदीश कुमार
मो0 9628825379
संरक्षक संजय गुप्ता
7860079888
उप संरक्षक- आदित्य मौर्या
प्रधान संम्पादक- राकेश मौर्या
उप संम्पादक – नियामअतुल्ला
समाचार संम्पादक- विनय कुमार
सह संपादक- तबरेज नियाजी
कार्यकारी सम्पादक
राजेश गौतम, सतीश चौहान
प्रबन्ध संम्पादक –रंजीत कुमार
@-swadeshbharatnews@gmail-com
समस्त वादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा